कैबिनेट का फैसला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: आगामी एथनाल वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने एथनाल के संशोधित मूल्य की घोषणा की है। गन्ने से तैयार एथनाल की कीमतों में 1.47 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पेट्रोल में एथनाल मिश्रण कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को एथनाल खरीद की अनुमति दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में गन्ना, चीनी और शीरा से अलग-अलग तैयार एथनाल की कीमतों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत हैवी शीरे से तैयार होने वाले एथनाल की कीमत 45.69 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 46.66 रुपये कर दिया गया है। जबकि बी हैवी से तैयार एथनाल का मूल्य 57.61 रुपये से बढ़ाकर 59.08 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके मुकाबले गन्ने के रस, चीनी और चीनी सिरप से तैयार किए जाने वाले एथनाल का मूल्य 62.65 रुपये से बढ़ाकर 63.45 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की योजना साल 2025 तक पेट्रोल में एथनाल का मिश्रण बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का है।

एथनाल के संशोधित मूल्य को कैबिनेट की मंजूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: जूट उद्योग के प्रोत्साहन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण नियमों को मंजूरी दी। इसके तहत खाद्यान्नों को 100 प्रतिशत तो 20 प्रतिशत चीनी को जूट की बोरियों में अनिवार्य रूप से पैक करना होगा। सरकार के इस फैसले से जूट उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और 3.7 लाख से अधिक श्रमिकों को राहत मिलेगी। साथ ही 40 लाख किसानों की आजीविका में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा पर्यावरण सुरक्षा में भी मदद मिलेगी, क्योंकि जूट एक प्राकृतिक, बायोडिग्रेडेबल, नवीकरणीय और पुन: उपयोग किए जाने वाला फाइबर है। जूट पैकेजिंग सामग्री में पैकेजिंग के आरक्षण से देश में वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग 66.57 प्रतिशत कच्चे जूट की खपत हुई। जूट उद्योग का सामान्य रूप से भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में और विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र यानी पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में महत्वपूर्ण स्थान है। यह पूर्वी क्षेत्र, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख उद्योग है।

पिछले सात सालों 2014-15 से 2020-21 में एमएसपी के बराबर के मूल्य किसानों से काटन की खरीद की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने सीसीआइ को 17,408.85 करोड़ रुपये देने का फैसला किया। सीसीआइ के इस फैसले से काटन किसानों को काफी राहत मिली थी।

काटन खरीद के बदले सीसीआइ को 17,408.85 करोड़ रुपये